



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 1995/पौष 30, 1916

No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 1995/PAUSA 30, 1916

कार्यालय लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय

(कार्यालय और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1995

मा. का. नि. 39(अ)--- केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36C के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के बिंदु (ग) द्वारा प्रदत्त यक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गढ़वालों के बेतन और भल्ते तथा सेवा की प्राप्ति) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदर्यों के बेतन और भल्ते तथा सेवा की प्राप्ति) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये 31 मार्च, 1989 से प्रवत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपनियम (1) के अधीन पेशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु नियम के अधीन देय पेशन की कुल रकम, जिसके साथ पेशन के संगतित भाग, यदि कोई हो, महित पेशन की गेसी रकम भी है जो अधिकरण में पद धारण करते ममय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विद्वित पेशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।”

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेशन का 31-3-89 से अर्थात् उस तारीख से पुनरीक्षण करने का विनियम किया है जिससे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय पेशन का पुनरीक्षण किया गया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का तदनुमार भूतलक्ष्मी प्रभाव से, अर्थात् 31 मार्च, 1989 से ही संशोधन किया जा रहा है।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि वह अधिसूचना को भूतलक्ष्मी प्रभाव देने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. ए-12018/10/90-एटी]  
श्रीमती भरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम दिनांक 10 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 644 (ई) को अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए —

- (i) सं. सा. का. नि. 583(अ) दिनांक 18-6-1987
- (ii) सं. सा. का. नि. 9(अ) दिनांक 6-1-1988
- (iii) सं. सा. का. नि. 79(अ) दिनांक 4-2-1988
- (iv) सं. सा. का. नि. 324(अ) दिनांक 3-3-1988
- (v) सं. सा. का. नि. 120(अ) दिनांक 22-2-1989
- (vi) सं. सा. का. नि. 417(अ) दिनांक 31-3-1989
- (vii) सं. सा. का. नि. 72(अ) दिनांक 30-1-1992
- (viii) सं. सा. का. नि. 41(अ) दिनांक 1-2-1993

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1995

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 35 read with section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (3 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman, and Members) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 31st day of March, 1989.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.”

## EXPLANATION MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the Pension of Members of Central Administrative Tribunal with effect from 31-3-1989, that is the date from which pension admissible to Chairman and Vice-Chairmen of the Central Administrative Tribunal has been revised. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly, with retrospective effect, i.e. on and from the 31st March, 1989.

2. It is certified that no Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

[No. A-12018/10/90-AT]

SMT. SARITA PRASAD, Lt. Secy.

**Footnote :—**The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification No. GSR 644(E), dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification—

- (i) No. GSR 583(E), dated 18-6-1987.
- (ii) No. GSR 9(E), dated 6-1-1988.
- (iii) No. GSR 79(E), dated 4-2-1988.
- (iv) No. GSR 324(E), dated 3-3-1988.
- (v) No. GSR 120(E), dated 22-2-1989.
- (vi) No. GSR 417(E), dated 31-3-1989.
- (vii) No. GSR 72(E), dated 30-1-1992.
- (viii) No. GSR 41(E), dated 1-2-1993.